

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 634]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर 2019 — आश्विन 4, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 सितम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-19/2019/18. — छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2019 कहलायेंगे।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- परिभाषाएं.**— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - “अधिनियम” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984);
 - “क्षेत्र” से अभिप्रेत है किसी बस्ती की ऐसी शासकीय भूमि, जिसे नगरीय निकाय द्वारा शहरी गरीबों के बसाहट हेतु घोषित की गई है;
 - “प्रारूप” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप;
 - “धारा” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।
(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ, जो इनमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

3. **रजिस्टर तथा स्थल योजना तैयार करना.—** (1) प्राधिकृत अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु प्रत्येक क्षेत्र के लिये प्ररूप-क में एक रजिस्टर तैयार करेगा।
 (2) प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्र के प्रत्येक कुटुम्ब के अधिभोग के अधीन भू-खण्ड को दर्शाने वाली स्थल योजना तैयार करवायेगा।
 (3) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, अधिनियम लागू करने के प्रयोजन हेतु, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अविलंब, प्रत्येक क्षेत्र के लिए इमेज की व्यवस्था की जायेगी, जो उपलब्ध सेटेलाईल इमेज पर आधारित होगी। इन इमेज के आधार पर साइट प्लान, जो प्रत्येक परिवार के अधिभोग वाले भू-खण्ड को दर्शाता हो, को फ्रिज किया जायेगा, और इसी के आधार पर हितग्राही की भूमि को प्रमाणित किया जायेगा। हितग्राही के बायोडाटा को यूनिक आईडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदत्त आधार कार्ड से जोड़ दिया जायेगा।
4. **भूमिहीन व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण.—** प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में डोर-टू-डोर सर्वे कराया जायेगा और उक्त रजिस्टर में स्वप्रेरणा से ऐसे प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति का मामला पंजीकृत किया जायेगा, जिसके पक्ष में भूमि का, पट्टाधृति अधिकारों के अंतर्गत व्यवस्थापित होना मान लिया गया है।
5. **अविवादित मामलों का अभिलेखन.—** प्राधिकृत अधिकारी स्थल का निरीक्षण करेगा और ऐसी जांच करेगा, जैसा कि वह उचित समझे तथा समस्त अविवादित मामलों के संबंध में ऐसे पट्टाधृति अधिकारों को अभिलिखित करेगा।
6. **विवादित मामलों का पंजीकरण.—** प्राधिकृत अधिकारी एक पृथक् रजिस्टर में समस्त विवादित मामलों की पंजी करेगा तथा अपने विनिश्चय का सारांश प्ररूप-क में रजिस्टर में अभिलिखित करेगा। ऐसे समस्त मामलों का विनिश्चय, प्रत्येक मामले में सुनवाई करने तथा समुचित जांच करने के पश्चात् किया जायेगा।
7. **कब्जा वाली अतिरिक्त भूमि का नियमितिकरण.—** (1) अधिनियम की धारा 3-ख के अंतर्गत, कब्जा वाली अतिरिक्त भूमि के नियमितिकरण हेतु, प्रकरणों के संबंध में, इस प्रयोजन हेतु आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किये जाने पर, संयुक्त दल के द्वारा, जिसमें अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, नजूल अधिकारी, स्थानीय नगरीय निकाय के अधिकारी, तथा ग्राम एवं नगर निवेश के अधिकारी सम्मिलित होंगे, प्रत्येक प्रकरण में, स्थल का निरीक्षण किया जायेगा।
 (2) इस संबंध में संयुक्त दल के संतुष्ट हो जाने पर कि कब्जा वाली अतिरिक्त भूमि, अधिनियम की धारा 3-ख के अंतर्गत नियमितिकरण हेतु योग्य है, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप-ख पर अतिरिक्त भूमि के नियमितिकरण के लिये कब्जाधारी व्यक्ति को नियम 14 के अनुसार विकास प्रभार के भुगतान के लिये मांग पत्र जारी करेगा।
 (3) मांग अनुसार विकास प्रभार का सम्यक् रूप से भुगतान किये जाने के पश्चात्, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियम 3 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत तैयार किये गये स्थल योजना में सम्यक् संशोधन किया जायेगा और, यथास्थिति, नियम 10 या 11 के अंतर्गत कब्जे की अतिरिक्त भूमि के संबंध में कब्जाधारी के पक्ष में नियमितिकरण का पट्टा प्रदान किया जायेगा।
 (4) प्ररूप-क में रजिस्टर में आवेदक/मूल पट्टाधारी के नाम के विरुद्ध अतिरिक्त भूमि पर कब्जे के नियमितिकरण संबंधी समुचित प्रविष्टि, प्राधिकृत अधिकारी लाल स्याही में अपने हस्ताक्षर करेगा जिसमें नियमित की गई अतिरिक्त भूमि का रकबा और नियमितिकरण की तारीख का उल्लेख होगा।
8. **अवैध/अनियमित पट्टा हस्तांतरण का नियमितिकरण.—** (1) अधिनियम की धारा 5-क के अंतर्गत अवैध/अनियमित पट्टा हस्तांतरण के नियमितिकरण हेतु प्रकरणों के संबंध में, इस प्रयोजन हेतु आवेदन की प्राप्ति पर या किसी भी स्रोत से शिकायत की प्राप्ति पर या स्व-प्रेरणा से कार्यवाही करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संयुक्त दल के सदस्यों को जो तत्पश्चात स्थल निरीक्षण करेंगे को सूचित किया जायेगा।
 (2) यदि हस्तांतरण किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया था, जो भूमिहीन नहीं है या अन्यथा अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही बनने की पात्रता नहीं रखता है, तो पट्टे के हस्तांतरण को निरस्त कर तथा संबंधित व्यक्ति को कब्जे की भूमि पर से हटाकर भूमि को कब्जा मुक्त किया जायेगा।
 (3) तथापि यदि संयुक्त दल संतुष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भूमि का कब्जाधारी है, वह भूमिहीन है तथा अन्यथा अधिनियम की धारा 5-क के अंतर्गत हितग्राही बनाये जाने के योग्य है, तो ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मूल पट्टाधारी को प्रदत्त पट्टा निरस्त कर, प्ररूप-ख में भूमि के पट्टे के अनियमित हस्तांतरण के नियमितिकरण हेतु नियम 14 के अन्तर्गत विकास प्रभार का भुगतान करने हेतु संबंधित कब्जेधारी को मांग पत्र जारी किया जायेगा।

- (4) मांग के अनुसार विकास प्रभारों के सम्यक् रूप से भुगतान के उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार तैयार किये गये स्थल योजना में सम्यक् संशोधन किया जायेगा और, यथास्थिति, नियम 10 या 11 के अंतर्गत पट्टाधिकार वर्तमान कब्जाधारी के पक्ष में प्रदान किया जायेगा।
- (5) प्ररूप-क में रजिस्टर में मूल पट्टाधारी के नाम के विरुद्ध लाल स्याही में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से समुचित प्रविष्टि की जायेगी जिसमें पट्टे के अनियमित अन्तरण के नियमितिकरण के तथ्य, नाम तथा नये पट्टाधारी के अन्य विवरण, नियमितिकरण की तारीख आदि लेखबद्ध की जायेगी।

9. **भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन का नियमितिकरण.**— (1) अधिनियम की धारा 5-क के अंतर्गत मूल पट्टे की शर्तों के उल्लंघन में किये गये भूमि प्रयोजन के अवैध/अनियमित परिवर्तन के नियमितिकरण से संबंधित प्रकरणों में, इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर या किसी भी स्त्रोत से शिकायत प्राप्त होने पर या स्व-प्रेरण से कार्यवाही करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संयुक्त दल के सदस्यों को जो तत्पश्चात स्थल का निरीक्षण करेंगे को सूचित किया जायेगा।

- (2) यदि भूमि के प्रयोजन में किया गया परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार योग्य नहीं हो या वह प्रभावशील मास्टर प्लान का उल्लंघन करता हो, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पट्टाधारी को नोटिस जारी कर, पट्टा विलेख के अनुसार भूमि को मूल प्रयोजन के रूप में लाने हेतु निर्देशित किया जायेगा और यदि विलेख के उल्लंघन में पट्टाधारी द्वारा उल्लंघन जारी रहता है, तो पट्टा निरस्त किया जायेगा और उस कब्जाधारी को वहाँ से हटाया जायेगा।
- (3) तथापि, यदि संयुक्त दल संतुष्ट हो जाता है कि भूमि प्रयोजन में किया गया परिवर्तन, अधिनियम की धारा 5-क के अंतर्गत स्वीकार योग्य है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भूमि पर पट्टे के अनियमित अन्तरण के नियमितिकरण हेतु वर्तमान कब्जाधारी पर नियम 14 के अनुसार विकास प्रभार के भुगतान के लिये प्ररूप-ख में मांग पत्र जारी किया जायेगा।
- (4) मांग के अनुसार विकास प्रभार का सम्यक् रूप से भुगतान किये जाने पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियम 3 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत तैयार किये गये स्थल योजना में सम्यक् संशोधन किया जायेगा और भूमि प्रयोजन में परिवर्तन को अनुज्ञात किया जायेगा।
- (5) प्ररूप-क में रजिस्टर में मूल पट्टाधारी के नाम के विरुद्ध लाल स्याही में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से सम्यक् प्रविष्टि की जायेगी, जिसमें नियमितिकरण की तारीख तथा नई भूमि के प्रयोजन को दर्शाते हुए भूमि के प्रयोजन के अनियमित परिवर्तन के नियमितिकरण के तथ्यों को लेखबद्ध किया जायेगा।

10. **स्थायी पट्टे का प्रदान किया जाना.**— स्थायी पट्टा विलेख, 30 वर्ष की कालावधि के लिये प्ररूप-ग में जारी किया जायेगा।

11. **अस्थायी पट्टा विलेख.**— यदि प्राधिकृत अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि लोकहित में अन्यत्र संपूर्ण व्यवस्थापन आवश्यक है, तो ऐसे व्यवस्थापन के गृह स्थल के अधिभोगियों को उनके अधिभोग के गृह स्थल के लिये प्ररूप-घ में अस्थायी पट्टे विलेख जारी किये जायेंगे। जब अस्थायी पट्टाधारक को वैकल्पिक स्थल पर व्यवस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे दिया गया अस्थायी पट्टा विलेख यथाशीघ्र निरस्त कर दिया जायेगा।

12. **निवासगृहों का हटाया जाना.**— (1) विद्यमान कब्जे की किसी भूमि को लोकहित में खाली कराये जाने के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति होगी।

(2) उच्च स्तरीय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) **नगर पालिक निगम वाले शहरों के लिये:—**

(1)	कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(3)	क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(4)	आयुक्त, नगरपालिक निगम	सदस्य
(5)	नगर तथा ग्राम निवेश का स्थानीय अधिकारी	सदस्य

(ख) नगरपालिका वाले शहरों के लिये:-

(1)	अपर कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	अपर पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(3)	क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(4)	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्	सदस्य
(5)	नगर तथा ग्राम निवेश का जिले का भारसाधक अधिकारी	सदस्य

(ग) नगर पंचायत वाले शहरों के लिये:-

(1)	क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अध्यक्ष
(2)	क्षेत्र का एस.डी.ओ. (पुलिस)	सदस्य
(3)	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत	सदस्य
(4)	नगर तथा ग्राम निवेश का जिले का भारसाधक अधिकारी	सदस्य

- (3) उप-नियम (1) के अधीन गठित उच्च स्तरीय समिति, लोकहित में निवास स्थलों को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही करेगी :-

(एक) ऐसे भूमिहीन व्यक्ति के मामले में, जिसने किसी सार्वजनिक उद्यान में या किसी सड़क की ओर या सड़क या निवास स्थान के बीच में या अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि पर किसी आवास स्थल को अधिभोग में रखा है, उसे ऐसे स्थान से हटाया जाएगा और उसे किसी वैकल्पिक स्थान पर पट्टाधृति अधिकार प्रदान करके अन्यत्र बसाया जायेगा।

(दो) यदि स्थायी पट्टाधारियों को हटाना तथा अन्यत्र बसाना लोकहित में आवश्यक समझा जाये, तो उच्च स्तरीय समिति, ऐसे पट्टाधारकों को सुनवाई का अवसर देगी तथा उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, कब्जेधारी को अन्यत्र बसाने का विनिश्चय करेगी।

13. **वैकल्पिक व्यवस्थापन पर स्थायी पट्टे का प्रदाय.-** जब किसी अस्थायी पट्टाधारक को किसी वैकल्पिक स्थल पर व्यवस्थापित किया जाता है तो उसे स्थायी पट्टा तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि वह अस्थायी पट्टे के अधीन उसके द्वारा कब्जे की भूमि को खाली नहीं कर देता।

14. **अतिरिक्त कब्जा भूमि, अवैध/अनियमित पट्टा हस्तांतरण के मामलों का नियमितिकरण, भूमि प्रयोजन में परिवर्तन एवं पट्टाधृति अधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तित करने पर देय विकास प्रभार.-** (1) भूमि पर पट्टाधारी के स्वयं काबिज होने तथा भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में, पट्टाधृति अधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तित करने हेतु देय विकास प्रभार की गणना, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में प्रचलित छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र में निर्धारित दर के अनुसार की जाकर, देय होगी।

(2) पट्टाधारी के द्वारा भूमि का प्रयोजन व्यावसायिक रूप में परिवर्तन का नियमितिकरण, भूमि पर पट्टाधारी के द्वारा अतिरिक्त कब्जे की भूमि का नियमितिकरण एवं अतिरिक्त कब्जा की भूमि अन्य व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग का नियमितिकरण में विकास प्रभार की गणना, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में प्रचलित छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र में निर्धारित दर के अनुसार की जाकर, देय होगी।

(3) नियम 8 के अधीन प्रकरणों में, जहाँ पट्टाधारी पट्टा अधिकारों के अवैध/अनियमित हस्तांतरण के माध्यम से भूमि के अधिभोग में है, देय विकास प्रभार की गणना अधिनियम की धारा 5-क के अनुसार की जायेगी, जो आवासीय प्रयोजन की भूमि के लिये बाजार मूल्य का एक सौ पच्चीस प्रतिशत होगी।

(4) ऐसे मामलों में जहाँ भूमि के प्रयोजन में पट्टाधारी द्वारा परिवर्तन किया गया है, वहाँ नियमितिकरण हेतु देय विकास प्रभार की गणना अधिनियम की धारा 5-क के अनुसार की जायेगी, जो गैर-आवासीय प्रयोजन की भूमि के लिये बाजार मूल्य का दो सौ प्रतिशत होगा।

(5) पट्टाधारी से वसूल किया गया विकास प्रभार, शासकीय कोष में जमा किया जायेगा।

15. **कब्जे की भूमि को खाली कराया जाना सुनिश्चित करना.-** यदि भूमिहीन व्यक्ति वैकल्पिक स्थल पर व्यवस्थापित हो जाता है, तो उसे कोई पट्टा तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह कब्जे में ली गई भूमि को खाली नहीं कर देता।

- 16. पट्टे की भूमि का नवीनीकरण.**— (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टे का नवीनीकरण, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा :
- (क) निकट भविष्य में उस भूमि की आवश्यकता किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अपेक्षित न हो।
 - (ख) पट्टाधारी द्वारा सभी विकास प्रभार तथा नगरीय निकाय की अन्य समस्त देनदारियों का सम्यक् रूप से भुगतान किया गया हो।
 - (ग) पट्टाधारी द्वारा अधिनियम या इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया हो।
- (2) नियम 10 के अधीन प्रदत्त पट्टे का अवधि विस्तार (नवीनीकरण) तीस वर्षों की अवधि के लिए किया जायेगा।
 - (3) पट्टे का नवीनीकरण करते समय देय विकास प्रभार में वृद्धि की जा सकेगी तथा ऐसी अन्य शर्तें भविष्य के लिए जोड़ी जा सकेंगी, जैसा कि पट्टाकर्ता उचित समझे।
 - (4) पात्र हितग्राहियों के कब्जे वाली भूमियों के संबंध में नया पट्टा अभिलेख प्रदान किया जायेगा।
- 17. पट्टाधृति अधिकार को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित किया जाना.**— (1) पट्टाधारी से आवेदन प्राप्त होने पर, पट्टाधृति अधिकार को भूमि स्वामी अधिकार में निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत परिवर्तित किया जा सकेगा :—
- (क) मूल पट्टाधारी अथवा उसकी मृत्यु की स्थिति में, उसका वैधानिक उत्तराधिकारी का उस भू-खण्ड पर अधिभोग जारी हो और वह वहीं निवासरत हो;
 - (ख) मूल पट्टे की शर्तों तथा निर्बंधनों का सम्यक् रूप से अनुपालन हुआ हो;
 - (ग) पट्टाधारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करना होगा कि उसके पट्टाधृति अधिकार को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित किया जाये तथा वह ऐसे परिवर्तन से संबंधित समस्त प्रभारों, जैसा कि लागू हो, के भुगतान करने हेतु सहमत है।
- (2) ऐसे मामलों में, जहाँ पट्टाधारी को प्रदत्त पट्टे के अलावा अतिरिक्त कब्जे की भूमि कब्जे में रखा हो अथवा जहाँ अवैध/अनियमित अंतरण की भूमि अंतरित की गई हो तथा भूमि का प्रयोजन परिवर्तित किया गया हो, तो भूमि स्वामी अधिकारों के प्रदान किये जाने हेतु आवेदन का विचारण अनियमितता के नियमितिकरण के साथ ही किया जायेगा।
 - (3) भूमि-स्वामी अधिकार प्रदान करने के विलेख का निष्पादन छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा इसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु विहित प्रारूप में किया जायेगा।
- 18. भूमि का अवैध/अनियमित हस्तान्तरण तथा भूमि प्रयोजन के परिवर्तनों के मामलों में सत्यापन हेतु आधार दस्तावेज.**— भूमि के अवैध/अनियमित हस्तान्तरण तथा भूमि के प्रयोजन के परिवर्तन के मामलों में सत्यापन हेतु आधार दस्तावेज निम्नलिखित होंगे :—
- (क) केन्द्रीय निर्वाचन आयोग तथा/अथवा राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची;
 - (ख) विद्युत देयक/विद्युत संयोजन का दस्तावेज;
 - (ग) टेलीफोन बिल;
 - (घ) स्थानीय नगरीय निकाय का संपत्तिकर/समेकित कर पंजी;
 - (ङ) जलकर भुगतान दस्तावेज;
 - (च) भवन अनुज्ञा/दुकान अनुज्ञा;
 - (छ) अधिनियम के अधीन प्रदत्त पट्टाधृति पट्टे;
 - (ज) अंतिम तिथि के पूर्व में जारी आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस।
- 19. निरसन एवं व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं :
- परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

प्ररूप "क"
(नियम 3 देखिये)

स. क्र.	मोहल्ला का नाम	अधिभोगी का नाम	आवास क्रमांक	अधिभोग का क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अधिभोगी के कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या	कुटुम्ब में वयस्क महिलाओं की संख्या	क्या अधिभोगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है	अधिभोगी का व्यवसाय तथा उसके द्वारा कथन किये गये अनुसार उसकी वार्षिक आय	अधिभोग की कालावधि
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

यदि अधिभोगी नगरीय क्षेत्र में कोई भूमि धारण करता है तो उसका ब्यौरा	शपथ-पत्र पर अधिभोगी का कथन	यदि अधिभोगी के पास राशन कार्ड/आधार कार्ड है तो उसका ब्यौरा	साक्षी के रूप में नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत समुचित अधिकारी के हस्ताक्षर	सक्षम अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण की तारीख तथा उसका संक्षिप्त मत
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

सक्षम अधिकारी का आदेश	व्यवस्थापित भूखण्ड का क्षेत्रफल	वार्षिक विकास प्रभार	अभ्युक्ति	प्रविष्टि
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

प्ररूप "ख"
(नियम 7, 8 एवं 9 देखिये)

मांग पत्र

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2019 के अधीन

क्र.

दिनांक:

श्रीमति/श्री

भू-खंड क्र. ; (बस्ती का नाम)

वार्ड क्र. ; (शहर का नाम)

विषय : विकास प्रभार का भुगतान

नीचे उल्लिखित प्रयोजनार्थ आपको एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि इस मांग पत्र के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर में रु. (रुपये) जमा करें, असफल होने पर नियमितिकरण की प्रक्रिया समाप्त कर दी जायेगी और आपके विरुद्ध समुचित दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

मांग का प्रयोजन (उचित डब्बे में <input checked="" type="checkbox"/> निशान लगावें)		
<input type="checkbox"/>	अधिभोग के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का नियम 7 के अधीन नियमितिकरण हेतु विकास प्रभार	
<input type="checkbox"/>	भूमि का अनियमित हस्तांतरण का, नियम 8 के अधीन नियमितिकरण हेतु विकास प्रभार	
<input type="checkbox"/>	भूमि प्रयोजन में अनियमित परिवर्तन का, नियम 9 के अधीन नियमितिकरण हेतु विकास प्रभार	

प्राधिकृत अधिकारी का
हस्ताक्षर नाम व पदमुद्रा

प्ररूप "ग"
(नियम 10 देखिये)

पट्टेदार का
संयुक्त छाया
चित्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्ता के रूप में निर्दिष्ट है) की ओर से कार्य करते हुए जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा श्री/श्रीमती आत्मज/ पत्नी एवं श्री/श्रीमती आत्मज/पत्नी निवासी जिसका छायाचित्र तथा बायें हाथ के अंगूठे का निशान पार्श्व में लगे हैं (जो इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार के रूप में निर्दिष्ट है) को नीचे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि वर्ष की कालावधि के लिये पट्टाधृति अधिकार पर धारण करने के लिये छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और नीचे दर्शाये गये निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, एतद्वारा पट्टा प्रदान किया जाता है :-

1. पट्टेदार उसे आबंटित (उक्त) भूमि का उपपट्टा, विक्रय पत्र, दान पत्र, बंधक के तौर पर या अन्य किसी रीति से समनुदेशन या अंतरण नहीं करेगा या उक्त भूमि का कब्जा नहीं छोड़ेगा जिससे कि उसका कोई विभाजन हो जाये या पट्टाधृति अधिकार के स्वरूप में अन्यथा परिवर्तन हो जाये।
2. पट्टेदार प्राधिकृत अधिकारी की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना, निवास गृह से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये उक्त भूमि का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने के लिये अनुज्ञात नहीं करेगा।
3. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के उल्लंघन में पट्टेदार द्वारा किये गये किसी भी अंतरण से पट्टाधृति अधिकार रद्द हो जायेगा।
4. यदि अधिनियम की धारा 3-क की उप-धारा (3) के अधीन यदि लोकहित में बस्ती के अन्यत्र पुनर्व्यवस्थापन का विनिश्चय किया जाता है, तो पट्टाधृति अधिकार रद्द कर दिया जाएगा तथा पट्टेदार का अन्यत्र व्यवस्थापन किया जायेगा।
5. पट्टेदार बस्ती विकास प्रभार 10 वर्ष की कालावधि हेतु प्रतिवर्ष रूपये प्रति वर्गफुट की दर से समान किश्तों में भुगतान करेगा।
6. पट्टाकर्ता एतद्वारा प्रसंविदा करता है कि वह एतद्वारा मंजूर की गई अवधि के अन्त में और तत्पश्चात् इसी प्रकार समय-समय पर वर्षों की प्रत्येक क्रमवर्ती अवधि के अन्त में, जो कि पट्टेदार (पट्टाधारी) के निवेदन पर तथा खर्च से मंजूर की जायेगी, उक्त भूमि को वर्ष की अवधि के लिये पट्टे का नवीनीकरण करके उसके नाम से निष्पादित करेगा :

परंतु यह कि पट्टे के नवीनीकरण किये जाने के समय बस्ती विकास प्रभार बढ़ाया जा सकेगा और प्रत्येक नवीनीकृत पट्टे में इसमें वे निबंधन वे शर्तें अंतर्विष्ट होंगी जो कि लागू होती हों तथा ऐसी शर्तें होंगी जो कि पट्टाकर्ता द्वारा भविष्य के लिये उचित समझी जायें :

परंतु यह और कि इस संबंध में बस्ती विकास प्रभार तथा लागू शर्तों के मामले में प्रत्येक क्रमिक नवीनीकरण में पट्टाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।
जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रत्येक मामले में लिखे गये दिन तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
साक्षीगण

- 1.
- 2.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर

- 1.
- 2.

पट्टेदार के हस्ताक्षर.....
तथा बायें हाथ की अंगूठा निशानी.....
तारीख

अनुसूची

भूखण्ड क्रमांक मोहल्ला क्रमांक तथा नाम
 क्षेत्र/प्रिक्षेत्र का नाम तहसील तथा जिला क्षेत्रफल माप में
 वर्गफीट तथा सीमायें निम्नानुसार है :-

उत्तर में-
 दक्षिण में-
 पूर्व में-
 पश्चिम में-

प्ररूप "घ"
 (नियम 11 देखिये)

पट्टेदार का
 संयुक्त छाया
 चित्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्ता के रूप में निर्दिष्ट है) की ओर से कार्य करते हुए जिला के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा श्री/श्रीमती आत्मज/पत्नी श्री/श्रीमती आत्मज/पत्नी निवासी (जो इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार के रूप में निर्दिष्ट है) को इसके नीचे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पट्टाधृति अधिकार पर धारण करने के लिये, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और इसमें इसके नीचे दर्शाये गये निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, एतद्वारा पट्टा प्रदान किया जाता है :-

1. पट्टेदार उक्त भूमि का समनुदेशन, अंतरण नहीं करेगा या कब्जा नहीं छोड़ेगा जिससे उसका कोई विभाजन हो जाये या निवास गृह में अन्यथा कोई परिवर्तन या परिवर्धन हो जाये।
2. पट्टेदार प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त भूमि का निवास गृह से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने के लिये अनुज्ञात नहीं करेगा।
3. यदि आनुकल्पिक स्थल उपलब्ध कराया जाता है तो पट्टा रद्द हो जायेगा। पट्टेदार निर्माण सामग्री आनुकल्पिक स्थल को ले जा सकेगा जिसके लिये उसे कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।
4. पट्टा का प्रत्येक वर्ष तब तक नवीनीकरण नहीं किया जायेगा जब तक की वैकल्पिक स्थल उपलब्ध नहीं हो जाता है।

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रत्येक मामले में लिखे गये दिन तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगण -

1. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
2. पट्टाधारी के हस्ताक्षर
 तथा बाये हाथ की अंगूठा निशानी.....

अनुसूची

भूखण्ड क्रमांक मोहल्ला क्रमांक तथा नाम
 क्षेत्र/प्रक्षेत्र का नाम तहसील तथा जिला क्षेत्रफल माप में
 वर्गफीट तथा सीमायें निम्नानुसार है :-

उत्तर में-
 दक्षिण में-
 पूर्व में-
 पश्चिम में-

अटल नगर, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 5-19/2019/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-19/2019/18 दिनांक 26-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 26th September 2019

NOTIFICATION

No. F 5-19/2019/18. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyan, 1984 (No. 15 of 1984), the State Government, hereby, makes the following rules for providing leasehold rights to landless persons, namely :-

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Rules, 2019.
 - (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No.15 of 1984);
 - (b) "Area" means such Government land of a slum that has been declared by the Municipality as a settlement for urban poor;
 - (c) "Form" means a form appended to these rules;
 - (d) "Section" means a Section of the Act.
 - (2) Words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as assigned to the said Act for them.
3. **Preparation of Register and Site Plan.**— (1) The Authorized Officer shall prepare a register for each area in Form "A" for the purpose of the Act.
 - (2) The Authorized Officer shall cause to be prepared a site plan showing plots of land in occupancy by each family of the area.
 - (3) The Authorized Officer shall, immediately on commencement of these rules, for the purpose of implementing the Act, arrange for image of every area based on the available satellite images. Based on these images, site plans showing the land in occupancy of every family shall be frozen and on this basis the land of the beneficiary shall be certified. The biodata of the beneficiary shall be linked to the Aadhaar number issued by the Unique Identification Authority of India (UIDAI).
4. **Registration of landless person.**— The authorized Officer shall get a door-to-door survey conducted in every area, and shall suo-moto register cases in the above register of each landless person in whose favour the land has been deemed to be settled under lease hold rights.
5. **Recording of undisputed cases.** — The Authorized Officer shall make spot inspection and shall hold such inquiries as he deems fit and record such lease hold rights in respect of all undisputed cases.
6. **Registration of disputed cases.**— The Authorized Officer shall register a separate case of all disputed cases and record a summary of his decision in the register in Form "A". All such cases shall be decided after hearing and making a proper inquiry in each case.
7. **Regularization of excess land under occupation.** — (1) In respect of cases under Section 3-B of the Act, for regularization of excess land in occupancy, on receipt of an application in this regard, on being informed by the Authorized Officer, the Joint Squad, which shall consist of the Additional Collector, the Deputy Collector, Nazul Officer, Official of the urban local body and Town and Country Planning, shall, in each case, conduct a site inspection.
 - (2) After the Joint Squad satisfies itself that the excess land in occupancy is fit for regularization under Section 3-B of the Act, the authorized officer shall raise a demand note on Form "B" for payment of Development Charges according to rule 14 on the occupant for regularization of the excess land.

- (3) After the Development Charges as demanded have been duly paid, the authorized officer shall get due modifications done in the site plan as prepared under sub-rule (2) of rule 3 and grant lease under rule 10 or 11, as the case may be, in favor of the occupant in respect of the excess land in occupancy that is being regularized.
 - (4) An appropriate entry under signature of the authorized officer shall be made in red ink against the name of the applicant/original lease-holder in the Register in Form "A", to record the fact of regularization of the excess land in occupancy, stating area of excess land and date of regularization.
8. **Regularization of Illegal/Irregular Transfer of Lease.** —(1) In respect of cases for regularization of illegal/irregular transfer of lease under Section 5-A of the Act, the Authorized Officer shall, on receipt of an application in this regard or on receipt of a complaint from any source or suo-moto, inform the members of the Joint Squad who shall then conduct a site inspection.
- (2) If the transfer was done in favor of a person who is not landless or otherwise undeserving for benefit under the Act, the transfer of lease shall be cancelled and the person shall be dispossessed of the occupied land, to make land possession free.
 - (3) If, however, the Joint Squad is satisfied that the person occupying the land is landless and otherwise deserving for benefit under Section 5-A of the Act, the authorized officer shall cancel the lease granted to the original person and raise a demand note in Form "B" for payment of Development Charges on the current occupant for regularization of the irregular transfer of lease on the land under rule 14.
 - (4) After the Development Charges as demanded have been duly paid, the authorized officer shall get due modifications done in the site plan as prepared under sub-rule (2) of rule 3 and grant lease under rule 10 or 11, as the case may be, in favor of the current occupant.
 - (5) An appropriate entry under signature of the authorized officer shall be made in red ink against the name of the original lessee in the Register in Form "A", to record the fact of regularization of the irregular transfer of lease, stating the name and other details of the new lessee and date of regularization.
9. **Regularization of Change of Land Use.** — (1) In respect of cases for regularization of illegal/irregular change of land use in violation of the terms of original lease under Section 5-A of the Act, the Authorized Officer shall, on receipt of an application in this regard, or on receipt of a complaint from any source or suo -moto, inform the members of the Joint Squad who shall then conduct a site inspection.
- (2) If the change of land use is unacceptable under the Act, or is violative of the Master Plan in force, the authorized officer shall issue a notice to the lessee to revert the land use according to the original terms of lease deed, and if the lessee continues with the violation the lease deed shall be cancelled and the occupant disposed.
 - (3) If, however, the Joint Squad is satisfied that the change in land use is acceptable under Section 5-A of the Act, the authorized Officer shall raise a demand note on Form "B" for payment of Development Charges according to rule 14 on the current occupant for regularization of the irregular transfer of lease on the land.
 - (4) After the Development Charges as demanded have been duly paid, the authorized officer shall get due modifications done in the site plan as prepared under sub-rule (2) of rule 3 and allow the change in land use.
 - (5) An appropriate entry under signature of the authorized officer shall be made in red ink against the name of the original lessee in the Register in Form "A", to record the fact of regularization of the irregular change in land use, stating the new land use and date of regularization.
10. **Grant of Permanent Lease.** — A permanent lease deed shall be issued in Form "C" for a period of 30 years.
11. **Temporary Lease Deed.**— If the Authorized Officer comes to the conclusion that it is necessary to resettle whole settlement elsewhere in the public interest, occupants of house sites in such settlement shall be issued temporary lease deeds for the house sites occupied by them in Form "D". The temporary lease deed shall be cancelled by the Authorized Officer as soon as the temporary lease holder is settled at an alternate site.

12. **Removal of dwelling House.** — (1) There shall be a High-Power Committee to decide on the question of securing the vacancy of any existing occupied land in the public interest.

(2) The High-Power Committee shall consist of the following, namely :—

(a) **For Municipal Corporation Towns :—**

(1)	Collector	Chairman
(2)	Superintendent of Police	Member
(3)	Sub-Divisional Officer (Revenue) of the area	Member
(4)	Commissioner, Municipal Corporation	Member
(5)	Local Officer of Town and Country Planning	Member

(b) **For Municipality Towns: —**

(1)	Additional Collector	Chairman
(2)	Additional Superintendent of Police	Member
(3)	Sub-Divisional Officer (Revenue) of the area	Member
(4)	Chief Municipal Officer, Municipal Council	Member
(5)	Officer of Town and Country Planning, in charge of the District	Member

(c) **For Nagar Panchayat Towns:-**

(1)	Sub-Divisional Officer (Revenue) of the area	Chairman
(2)	SDO (Police) of the area	Member
(3)	Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat	Member
(4)	Officer of Town and Country Planning, in charge of District	Member

- (3) The High-Power Committee constituted under sub-rule (1) shall take the following action in the matter of securing the vacancy of house sites in the public interest, namely:—

- (i) In the case of a landless person who occupies a house site in some public park or in the side of a road or in between road and dwellings or on the land required for other public purposes he shall be shifted from such location and resettled elsewhere by granting him leasehold right in the alternative location.
- (ii) If it is considered necessary in the public interest to shift the permanent lease holders and settle them elsewhere, the High-Power Committee shall give to such lease holder an opportunity of being heard and shall decide on shifting the occupant elsewhere after considering all the facts placed before it.

13. **Grant of permanent lease on alternate Settlement.**— When a temporary lease holder is resettled at some alternate site he shall not be granted a permanent lease unless he vacates the land occupied by him under temporary lease.

14. **Development Charge payable on regularization of cases of additional occupied land, illegal/irregular transfer of lease, change of land use and conversion of leasehold rights to bhumiswami rights.**—(1) In cases where the lease-holder is in occupation of the land and the land-use has not been changed, the development charge for conversion of leasehold rights to Bhumiswami rights shall be payable by calculating the rate determined in the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959) and Revenue book circular prevalent in the Revenue and Disaster Management Department ;

- (2) The development charge for regularization of change of land use to commercial by the leaseholder, regularization of additional land in occupation on land by the leaseholder and regularization of additional land in occupation which is being used for other commercial purpose shall be payable by calculating the rate determined in the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959) and Revenue book circular prevalent in the Revenue and Disaster Management Department.
- (3) In cases under rule 8, where the lease-holder is in occupation of the land through illegal/irregular transfer of lease rights, the development charge payable for regularization shall be calculated according to Section 5-A of the Act, which shall be one hundred twenty-five percent of the market rate for land under residential use.

- (4) In cases where the lease-holder has changed the land-use, the development charge payable for regularization shall be calculated according to Section 5-A of the Act, which shall be two hundred percent of the market rate for land under non-residential use.
 - (5) The development charges received from the lease-holder shall be deposited in the Government Treasury.
- 15. Securing vacation of occupied land.** — If a landless occupant is resettled at an alternate site, such a settler shall not be granted any lease till he vacates the land occupied by him earlier.
- 16. Renewal of Leasehold Land.** — (1) The lease granted under these rules may be renewed subject to the following conditions:
- (a) The land is not required for any other public purpose in the foreseeable future.
 - (b) The lessee has duly paid all development charges and other dues of the Municipality.
 - (c) The lessee has not violated any provision of the Act or these rules.
- (2) The term of extension of the lease granted under rule 10 shall be for a period of thirty years.
 - (3) At the time of the renewal of lease the Development Charges may be increased and such other conditions as may be deemed proper by the lessor for the future may be added.
 - (4) New Lease documents shall be issued in respect of lands under occupation of eligible beneficiaries.
- 17. Conversion of Leasehold Rights to Bhumiswami Rights.**—(1) On receipt of an application from the Lease-holder, the leasehold rights may be converted to Bhumiswami rights under the following conditions:-
- (a) The original leaseholder, or, in case he is dead, his legal heir, should still be occupying the plot of land and living on it;
 - (b) The terms and conditions of the original lease should have been duly complied with;
 - (c) The leaseholder must apply to the Authorized Officer requesting for conversion of leasehold rights to Bhumiswami rights, and agreeing to pay all charges related to such conversion as may be applicable.
- (2) In cases where the lease-holder is in possession of land in excess of what was leased to him, or where the land has been illegally/irregularly transferred, and where the land use has been changed, an application for grant of bhumiswami rights shall be considered alongside regularization of the irregularity.
 - (3) The deed for grant of bhumiswami rights shall be executed on the format prescribed under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, and the rules framed thereunder, for grant of bhumiswami rights.
- 18. Base documents for verification in cases of illegal/irregular transfer of land and change of land use.**— The following documents may be used as base documents for verification in cases of illegal/irregular transfer of land and change of land use:-
- (a) Electoral rolls of Central Election Commission and/or State Election Commission;
 - (b) Electricity Bill / Power connection document;
 - (c) Telephone Bill;
 - (d) Property Tax /Composite Tax Register of the urban local body;
 - (e) Water Tax payment document;
 - (f) Building Permission / Shop Permit;
 - (g) Lease Deed provided under the Act;
 - (h) Aadhaar Card / Driving Licence issued prior to the cut-off date.

19. **Repeal and saving.**— All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

FORM "A"
(See rule 3)

S.No.	Name of the Mohalla	Name of Occupant	House No.	Area occupied
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Number of family members of the occupant	Number of adult females in the family	Whether the occupant belongs to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Backward Classes	Occupation of the occupant and his annual income as stated by him	Period of occupation
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

If the occupant holds any land in the urban area details thereof	Statement of occupant on oath	If the occupant has a ration card / Aadhar Card details thereof	Signature of the appropriate officer authorized by Municipality as witness	Date of spot inspection by the competent officer and his brief opinion
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Order of the competent officer	Area of Plot settled	Annual Development Charges	Remarks	Entry
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

FORM "B"
(See rule 7,8 and 9)

DEMAND NOTE

Under Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana)
Rules, 2019

No.

Date:

Smt/Shri.....

Plot No.....; (Name of the Basti)

Ward No.....; (Name of the Town)

SUBJECT: Payment of Development Charges

You are hereby directed to deposit an amount of Rs. (Rupees))

For the purpose mentioned below, in the one week of the issue of this Demand Note, failing which the process of regularization will be terminated and appropriate penal action will be taken against you.

Purpose of Demand (Tick the appropriate box):

- ☐ Development Charges for Regularization under Rule 7 of excess land under occupation.
- ☐ Development Charges for Regularization under Rule 8 of irregular transfer of land.
- ☐ Development Charges for Regularization under Rule 9 of irregular change of land use.

Signature,

Name and Seal of the Authorized Officer

FORM "C"
(See rule 10)Joint
Photograph of
lessee

Lease is hereby granted by the Authorized Officer of District acting on behalf of the Governor of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Lessor) to Shri/Smt. Son/Wife of and Shri/Smt. Son/Wife of Shri R/o whose photograph and left hand thumb impression are affixed in the margin (hereinafter referred to as the lessee) to hold land Specified in the schedule appended hereunder on lease hold rights for a period of years subject to the provisions of the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhumihiin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984) and the rule made thereunder and the terms and conditions given below: —

1. The lessee shall not assign or transfer the land allotted to him by way of sublease, sale deed, gift, mortgage, or in any other manner, nor shall he part with the possession of the said land so as to cause any division therein or otherwise to alter the nature of the leasehold right.
2. The lessee shall not without the previous permission in writing of the Authorized Officer use or allow to be used the said land for purpose other than as a dwelling house.
3. Any transfer made by the lessee in contravention of sub-section (3) of Section 3 of the Act will lead to the cancellation of the leasehold right.
4. If, in Public interest it is decided to resettle the basti elsewhere under sub-section (3) of /..... Section 3-A of the Act, the leasehold right shall be cancelled and the lessee may be settled elsewhere.
5. The lessee shall pay for a period of 10 years basti development charges at the rate of rupees per square feet per year in equal installments.
6. The lessor hereby covenants that he will at the end of the term hereby granted and thereafter from time to time at the end of each successive further terms years as shall be granted at the request and cost of the lessee, execute it to him a renewed lease of the land for a period of year:

Provided that at the time of the renewal of lease the basti development charge may be increased and the renewed lease may contain such of the terms and conditions herein contained as applicable and such other conditions as may be deemed proper by the lessor for the future:

Provided further that the decision of lessor at each successive renewal about the basti development charges and the conditions imposed in this regard shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the day and year written in each case.

Witnesses—

1.....
2.....

Signature of Authorized Officer
on behalf of the Governor of
Chhattisgarh

1.....
2.....

Signature and left hand
thumb impression of the
lessee
dated

SCHEDULE

Plot No. Mohalla No. and Name Name of Area/Circle
Tehsil and District Measuring square feet and bounded as under :—

In the North by
In the South by
In the East by
In the West by

FORM "D"
(See rule 11)

Joint
Photograph of
lessee

Lease is hereby granted by the authorized Officer of the District acting on behalf of the Governor of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the lessor) to Shri/Smt. Son/Wife and Shri/Smt. Son/Wife of resident of (hereinafter referred to as the lessor) to hold the land specified in the schedule appended hereunder on a leasehold right subject to the provisions of Chhattisgarh Nagriya Kshetron Ke Bhumihiin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984) and the rules made there under and the terms and conditions herein after appearing:—

1. The lessee shall not assign transfer or part with the possession of the said land so as to cause any division thereof or otherwise make any alteration or addition in the dwelling house.
2. The lessee shall not without the previous permission of the Authorized Officer use or allow to be used the said land for a purpose other than as a dwelling house.
3. the lease shall stand cancelled if alternate site is made available. The lessee can take the material to alternate site for which he will not get any compensation.
4. The lease shall be renewed every year till alternate site is made available.

In witness whereof the parties here to have set their hands on the day and year written in each cases.

Witnesses—

1.....
2.....

Signature of Authorized
Officer on behalf of the
Governor of Chhattisgarh

1.....
2.....

Signature and left hand
thumb impression of the
lessee
dated

SCHEDULE

Plot No. Mohalla No. and Name Name of Area/Circle
Tehsil and District Measuring square feet and bounded as under :—

In the North by
In the South by
In the East by
In the West by